



ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहली बार बीकानेर आए। उन्होंने देशनोक के पलाना गांव की रोही में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का साफा पहनाकर स्वागत किया।

अब हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी-मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बात सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने की होगी

बीकानेर, 22 मई (कास)। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहली बार बीकानेर आए। जिला मुख्यालय से 22 किमी. दूर देशनोक के पलाना गांव की रोही में हुई विशाल जनसभा में मोदी करीब 40 मिनट बोले। उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हर हरकत का करारी जवाब दिया जायेगा। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को दो दृढ़ संदेश देते हुए कहा कि अब हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकायेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पुछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगांम में चली थीं, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे और उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। उन्होंने कहा कि देशवासियों के आशीर्वाद से और देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे

■ जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार द्वारा जारी नई औद्योगिक नीतियों का लाभ बीकानेर को भी मिलेगा। बीकानेरी भुजिया का स्वाद और बीकानेरी रसगुल्ले की मिठास विश्व भर में पहचान बनायेगी।

■ पलाना की सभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच साल पहले बालाकोट के बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में हुई थी। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पहली सभा यहाँ हो रही है। राजस्थान की वीरभूमि के तप से ऐसा संयोग बना है।

हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा रहता है लेकिन लहू गर्म रहता है और अब तो मोदी की नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान के साथ न तो व्यापार होगा, न ही बातचीत होगी। यदि बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को

वापस लेने की। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान ने अगर आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई-पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। मोदी ने कहा कि जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। यहां से कुछ ही दूर सीमापार पाकिस्तान का रहीमयार

खान एयरबेस अगले कई दिनों के लिए बंद हो चुका है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस-नहस कर दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए केन्द्र और राज्य की डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। राजस्थान की रीफाइनी का काम भी अंतिम चरण में है। अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार द्वारा जारी नई औद्योगिक नीतियों का लाभ बीकानेर को भी मिलेगा। बीकानेरी भुजिया का स्वाद और बीकानेरी रसगुल्ले की मिठास विश्व भर में अपनी पहचान और बढ़ाएंगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पांच साल पहले जब बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही हुई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक बार फिर विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्रम्प के मध्यस्थता के दावे को केवल कल्पना बताया

ट्रम्प की नाराज़गी सहने के लिये भारत को तैयार रहना पड़ेगा

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 मई। "अमेरिका केवल अमेरिका तक ही सीमित था।" विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने "ऑपरेशन सिंदूर" के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता में अमेरिका की मध्यस्थता पर पूछे गए सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की।

10 मई को युद्धविराम घोषित होने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप लगातार यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक फोन कॉल के जरिए दोनों देशों को व्यापार का प्रस्ताव देकर यह शांति स्थापित करवाई थी।

जो कोई भी भारत और पाकिस्तान के बीच की संवेदनशीलता और विवाद की पुष्टभूमि से जरा भी परिचित है, वह जानता है कि ट्रंप का यह दावा कितना अतार्किक और हास्यास्पद है। यही कारण है कि भारत, विशेष रूप से विदेश मंत्री एस. जयशंकर, लगातार यह स्पष्ट कर रहे हैं कि युद्धविराम केवल दोनों देशों के बीच आपसी सहमति से हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति के डील मेकर का क्रेडिट लेने की कोशिश को खारिज करने के निस्संदेह अलग नतीजे होंगे। इससे

■ ट्रम्प के दंभ भरे दावों को अब विश्व ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा, चाहे एक ही दिन में यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने की घोषणा हो, या रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी हो, या यमन के हूती को अपनी भारी नौ सेना से डराने का प्रयास हो, या ईरान के अयतुल्ला खमेनी को चेतावनी देने की कोशिश हो।

■ अतः बार-बार भारत-पाक के बीच अपनी मध्यस्थता से सीज़फायर कराने का दावा, ट्रम्प की मजबूरी बन गया है।

■ पर, भारत के विदेश मंत्री द्वारा ट्रम्प को इस "सीज़फायर" के लिए कोई भी श्रेय नहीं देना, ट्रम्प प्रशासन के लिए पचाना बहुत मुश्किल हो रहा है और इस खीज की गाज, भारत पर गिर सकती है।

पहले भी ट्रंप ने दावा किया था कि यदि वे चुने जाते हैं तो यूक्रेन युद्ध को एक दिन में समाप्त कर सकते हैं-जो पूरी तरह से एक कपोल कल्पना साबित हुई। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में असफल रहने के बावजूद, ट्रंप लगातार खुद को रूस-यूक्रेन शांति प्रक्रिया का नायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार-बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वे ट्रंप को ज्यादा तवज्जो नहीं देते।

ट्रंप द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाने की बार-बार की धमकियों के बावजूद, पुतिन ने यूक्रेन पर हमलों को और तेज कर दिया, यहां तक कि नागरिकों को भी निशाना बनाया, ठीक उसी समय, जब अमेरिका खुद को सक्रिय दिखाने की कोशिश कर रहा था। इस सबके बीच, ट्रंप की सबसे बड़ी विफलता तब सामने आई, जब उन्होंने

दावा किया कि यूक्रेन युद्ध केवल तब खत्म होगा, जब वे स्वयं पुतिन से बात करेंगे। उनके कैबिनेट सदस्य बार-बार उनकी "शानदार शक्तियत" की तारीफ करते रहे, उनका मत था कि ट्रंप का करिश्माई व्यक्तिगत पुतिन को शांति की ओर ले जाएगा।

हालांकि, पुतिन से दो घंटे लंबी टेलीफोन बातचीत के बाद भी शांति की कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिखी। उल्टा, रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए, जिससे यूक्रेनी जनता को और अधिक नुकसान उठाना पड़ा।

ट्रंप की इन लगातार कूटनीतिक विफलताओं के बीच, अमेरिका इतना व्यग्र है कि "सफलता" के मामूली से संकेत तक को लपक लेना चाहता है। हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका की सबसे शक्तिशाली नौसेना पर हमला किया, जिससे अमेरिकी प्रतिष्ठा को गहरा अघात पहुंचा। इसके बाद, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने भी अमेरिका और ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ईरान पर सीधा हमला किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विवाह के तीन माह बाद ही आत्महत्या, अभियुक्त पति को आजीवन कारावास

जयपुर, 22 मई। महिला उल्पीडन मामलों की विशेष अदालत ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर विवाह के तीन माह बाद ही विवाहिता के आत्महत्या करने के मामले में उसके पति विकास शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन

■ मृतका के भाई ने बयान दिया कि उसकी बहन ने बताया था कि उसका पति व ससुराल वाले दहेज के लिए मारपीट करते हैं।

अधिकारी आशुतोष कुमावत ने अपने आदेश में कहा कि एक लड़की के लिए उसका विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण पल होता है, जहां वह अपने पिता के संरक्षण से दूर सुंदर भविष्य का सपना देखते हुए अपने पति के साथ विदा होती है। उस समय लड़की के मन में यह विश्वास होता है कि उसका पति, उसके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सतपाल मलिक के खिलाफ चार्जशीट फाइल की सीबीआई ने

सतपाल मलिक, जम्मू-कश्मीर के गवर्नर थे तथा उस दौरान उन पर किरू में हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट का ठेका देने का आरोप लगाया गया था

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 22 मई। प्रतिशोध का मामला प्रतीत होने वाली एक कार्यवाही के अन्तर्गत, सी बी आई ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक एवं पांच अन्य के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। यह प्रकरण कोरू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के लिए 2200 करोड़ रु. के 'सिविल वर्क्स' का ठेका दिये जाने में हुए कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।

अधिकारियों ने आज कहा कि एंजेंसी ने 3 साल की जांच पड़ताल के बाद, अपने निष्कर्ष एक विशेष अदालत में पेश कर दिये हैं। इस प्रकरण मलिक एवं पांच अन्य लोग आरोपी बनाये गये हैं।

आज 'एक्स' पर डाली गई पोस्ट में मलिक ने कहा कि वे अस्पताल में भर्ती हैं तथा किसी से बात करने की स्थिति में नहीं हैं।

पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उनके

■ सीबीआई ने इस आरोप की तीन साल तफतीश करके यह चार्जशीट दाखिल की है।

■ सतपाल मलिक ने इस घटनाक्रम के बारे में कहा कि वे किसान पुत्र हैं तथा सरकार उन्हें डराना व दबाना चाहती है, पर, वे झुकेंगे नहीं।

■ सतपाल मलिक ने एक्स पर यह भी कहा कि वे अस्पताल में भर्ती हैं तथा अस्वस्थ हैं। अतः उन लोगों से बात नहीं कर पा रहे, जो उन्हें फोन कर रहे हैं।

पास बहुत से शुभचिन्तकों के कॉल आ रहे हैं, लेकिन वे बात नहीं कर पा रहे हैं। सी बी आई गत वर्ष फरवरी में इस केस के मामले में मलिक एवं अन्य के परिसरों की तलाशी ली थी।

सी बी आई ने 2022 में एफ आई आर दर्ज करने के बाद, एक बयान में कहा था कि यह केस 2019 में कोरू हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर (एच ई पी) प्रोजेक्ट के सिविल वर्क्स का 2200

करोड़ रु. का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दिये जाने में की गई कथित गड़बड़ी से संबंधित है।

मलिक, जो 23 अगस्त, 2018 से 30 अक्टूबर, 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे, ने दावा किया था कि उन्हें दो फाइलों पर स्वीकृति देने के लिए 300 करोड़ रु. की रिश्तत की पेशकश की गई थी। इनमें से एक फाइल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गलत जानकारी देने पर हाईकोर्ट ने 50 हजार का हर्जाना लगाया

जयपुर, 22 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में गलत तथ्य बताकर याचिका दायर करने को गंभीर माना है। इसके साथ ही, अदालत ने आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर पचास हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। जस्टिस समीर जैन की

■ अदालत ने पुरुषोत्तम दाधीच की पेपर लीक मामले में दायर अपराधिक याचिका खारिज की।

एकलपीठ ने यह आदेश पुरुषोत्तम दाधीच की आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि उस पर अपनी प्रेमिका के लिए पन्द्रह लाख रुपए में एसआई भर्ती का प्रश्न पत्र खरीदने का आरोप है। मामले में वह निचली अदालत में संरेख करने भी गया था, लेकिन अदालत ने उसे अपनी कस्टडी में नहीं लिया। मामले में दर्ज एफआईआर में भी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को बीस साल की सजा

जयपुर, 22 मई। पाँको मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विजय वर्मा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने

■ अभियुक्त ने दुष्कर्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था।

16 साल से कम उम्र की पीड़िता के साथ जबर्न दुष्कर्म कर उसकी अश्लील फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह गंभीर अपराध है और ऐसे अभियुक्त के साथ कोर्ट किसी तरह की नरमी नहीं बरत सकती।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने बनीपार्क पुलिस थाने में 22 जून 2022 को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सात प्रतिनिधिमंडल, जिनमें 32 प्रमुख राजनीतिक नेता शामिल हैं, पाकिस्तान की आतंकवादी हमलों में भूमिका को समझाने, विश्व यात्रा पर निकले

ये प्रतिनिधिमंडल लगभग तीन दर्जन देशों का दौरा करेंगे, पाकिस्तान की भूमिका के प्रमाण भी प्रस्तुत करेंगे

दुर्लभ एकता के इस प्रदर्शन के बावजूद भी इस पहल ने देश में राजनीतिक हलचल मचा दी है। सरकार पर आरोप लगे हैं कि उसने उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों के चयन में संबंधित दलों से औपचारिक सलाह-मशविरा नहीं किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर और सलमान खुर्शीद को कथित तौर पर पार्टी की औपचारिक सहमति के बिना शामिल किया गया, क्रिकेटर से राजनेता बने तुषमूल सांसद युसुफ पठान के मामले में भी ऐसा ही हुआ। इसने दलों के भीतर अंदरूनी कलह को जन्म दिया है और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार हरि देसाई, जो प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा

■ पर, एक प्रकार से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की मोदी सरकार की सराहनीय सफलता का मुँह में पूरा स्वाद आता उससे पहले कुछ किरकिरी आ गई, विपक्ष की कुछ पार्टियों की इस शिकायत से कि उनसे पूछा नहीं गया, उनके नेताओं को प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने से पहले।

■ इस आंतरिक विवाद का असर देश के कई राज्यों पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में "महायुति" गठबंधन में भी उथल-पुथल हो सकती है। शरद पवार व उनके भतीजे अजित पवार के दोनों धड़े अब एक होने के प्रयास में लगभग सफल हो गये हैं तथा देवेन्द्र फड़नवीस की सरकार को इससे मजबूती मिलेगी।

■ प्रतिनिधिमंडल भेजने की इस नीति से घटनाओं की एक शृंखला शुरू हो गई है, जिसका असर भारत के राजनीतिक घटनाक्रम में काफी समय तक प्रभावी रहेगा।

प्रचारक से लेकर अब तक की राजनीतिक यात्रा पर लंबे समय से नजर रखते आए हैं, ने इस कदम की

आलोचना की। उन्होंने कहा, "ऐसे समय में जब देश को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एकजुट चेहरा दिखाना चाहिए,

प्रधानमंत्री मोदी की यह रणनीति पार्टियों के भीतर आपसी कलह को जन्म दे रही है। एकता के नाम पर इस तरह का



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को बीकानेर जिले के देशनोक में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री ने देशनोक में 1 0 3 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया

उन्होंने बीकानेर वासियों को बीकानेर-मुम्बई एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी

देशनोक, 22 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को बीकानेर जिले के देशनोक में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हुए देशभर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशनोक रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर बीकानेर-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात भी दी।

उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से भी मिले और

■ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशनोक रेलवे परिसर में शहीदों के सम्मान में लगी प्रदर्शनी गैलरी का भी अवलोकन किया।

बच्चों द्वारा बनाई पेंटिंग्स की सराहना की। इस दौरान बच्चों ने भारत माता के जयघोष से परिसर को गुंजायमान कर दिया। प्रधानमंत्री ने स्टेशन परिसर में शहीदों के सम्मान में प्रदर्शनी गैलरी का अवलोकन किया। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय रेल मंत्री

अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल समेत, विभिन्न जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन व स्कूली बच्चे मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से 1300 से

अधिक स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसी क्रम में पुनर्विकसित किए गए 103 रेलवे स्टेशनों में राजस्थान के आठ रेलवे स्टेशन देशनोक, गोणामेड़ी, बूंदी, माण्डलगढ़, गोविंदगढ़, मण्डावर-महुआ रोड, फतेहपुर शेखावाटी और राजगढ़ शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देशनोक में करणी माता के दर्शन किए व आरती उतारी तथा मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा-अर्चना की। श्रीकरणी मंदिर निजी प्रत्यास के अध्यक्ष बादल सिंह देपावत ने प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह व मां करणी का साहित्य भेंट किया।

सात प्रतिनिधिमंडल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) इसी दौरान, नई दिल्ली में राजनीतिक विश्लेषक अन्य राज्यों में बदलते समीकरणों को लेकर कयास लगा रहे हैं। बिहार, जहाँ वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, में तुरंत कोई बड़ा बदलाव संभव नहीं दिखता, लेकिन स्थिति अब भी अस्थिर बनी हुई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और इंडिया ब्लाॅक दोनों के पक्ष और विपक्ष में नए राजनीतिक समीकरण उभर सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय सत्ता संतुलन पर असर पड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह वैश्विक कूटनीतिक पहल ऐसे समय में हो रही है, जब मोदी सरकार आगामी लोकसभा चुनावों से पहले अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को सुदृढ़ करने में जुटी है। आलोचकों का कहना है कि यह पहल, भले ही महत्वपूर्ण हो, घरेलू राजनीतिक हितों को भी साधने का प्रयास हो सकती है, खासकर वह भाजपा को एकमात्र ऐसी पार्टी के रूप में पेश कर सकती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एकजुट राष्ट्रीय मोर्चा बिना सकती है।

भौतीरी विवादों और राजनीतिक उठापटक के बावजूद, यह वैश्विक मिशन रणनीतिक सहयोगियों और प्रतिद्वंद्वियों दोनों के द्वारा बारीकी से देखा जा रहा है। यह मिशन पाकिस्तान की सीमा

पर आतंकवाद में संलिप्तता को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने प्रमाणित करने में कितना सफल होगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इसने भारत की राजनीतिक दिशा को अगले कुछ महीनों के लिए प्रभावित करना शुरू कर दिया है।

गलत जानकारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उसका नाम नहीं है और न ही मामले में उसकी सीधी भूमिका सामने आई है। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता पर अपनी महिला मित्र के लिए पेपर खरीद कर उपलब्ध कराने का आरोप प्रमाणित है। वह पुलिस गिरफ्त से दूर चल रहा है। ऐसे में उस पर 2.5 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है और अदालत ने उसकी गिरफ्तारी के स्याई वारंट जारी कर रखे हैं। इसके अलावा, उसने सरकारी वकील या अदालत में अपने सरेंडर को लेकर कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं, जिससे साबित होजा है कि वह सरेंडर के लिए अदालत में गया ही नहीं। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए। मामले की सुनवाई करते हुए, अदालत ने याचिका खारिज कर उस पर पचास हजार रुपये का हर्जाना लगाया है।

नीट पीजी सीट ब्लॉक करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नईदिल्ली, 21 मई। नीट पीजी में सीट ब्लॉकिंग की बढ़ ती शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एक अहम आदेश जारी किया है। अब देश की सभी प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटियों को काउंसिलिंग शुरू होने से पहले अपनी पूरी फीस संरचना (ट्यूशन फीस, हाॅस्टल फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट और अन्य शुल्क) सार्वजनिक करनी होगी।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि सीट ब्लॉकिंग की यह प्रथा केवल एक अनैतिक कार्य ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की कमजोरियों को उजागर

■ सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि काउन्सिलिंग से पहले सभी मैडिकल कॉलेजों को फीस बतानी होगी।

करती है। इसमें पारदर्शिता की कमी, शासन में समन्वय की कमी और नीतियों के ढाले पालन जैसी समस्याएं शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें - सभी यूनिवर्सिटियों को काउंसिलिंग से पहले फीस का खुलासा

करना अनिवार्य होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत, एक केन्द्रीकृत फीस रेगुलेशन सिस्टम विकसित किया जाएगा।

सीट ब्लॉक करने वाले छात्रों और कॉलेजों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी- जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट की जम्ती, भविष्य की नीट पीजी परीक्षाओं से अयोग्यता, और कॉलेज का ब्लैकलिस्ट होना।

ऑल इंडिया कोटा और राज्य स्तरीय काउंसिलिंग को समान कैलेंडर के तहत लाने का निर्देश ताकि, सीट ब्लॉकिंग को रोका जा सके। काउंसिलिंग के दूसरे राउंड के बाद छात्रों को बेहतर

‘ईडी सारी हदें पार कर रहा है’

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में शराब की दुकानों पर ईडी की रेड पर रोक लगाते हुए टिप्पणी की

■ तमिलनाडु हाईकोर्ट ने ईडी को एक हजार करोड़ रुपये के कथित घोटाले में राज्य विपणन निगम के खिलाफ मनी लॉण्डरिंग जांच की अनुमति दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

पीठ ने केन्द्रीय एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से कहा, आपका ईडी सारी हदें पार कर रहा है। आपका कार्यालय किसी निगम पर

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रखी जा रही है नये भारत की नींव-भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है

बीकानेर, 22 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के संकल्प ने एक नए भारत की नींव रखी है।

शर्मा, जिले के पलाना में आयोजित जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए भारत की सैन्य ताकत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और एयरबेसों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा देश भारतीय सेना के शौर्य से गौरवान्वित हो उठा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों के लिए वाइफ़्ट विलेज कार्यक्रम- 2 के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जिससे सीमावर्ती गांवों के लोगों को मुख्य धारा में लाकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने एवं आजीविका के पर्याप्त अवसर

■ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11 साल में 34 हजार किलोमीटर लम्बी रेल पटरियाँ बनीं, जो जर्मनी के कुल रेल नेटवर्क से बड़ा है।

प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने राम जल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते की सीमात के लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री का विशेष आभार प्रकट किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि देश में गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला- केवल चार जातियां हैं। इसी मंशा के अनुरूप, राज्य सरकार

इन चारों जातियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है।

सभा को सम्बोधित करते हुए, केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इस दौरान 34 हजार किलोमीटर लंबी रेल पटरियाँ बनी हैं, जो जर्मनी के कुल रेल नेटवर्क से भी अधिक है। 47 हजार किलोमीटर लंबी रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश में छोटे और मध्यम दर्जे के रेलवे स्टेशनों के विकास पर ध्यान दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले देश में एक साथ 1062 रेलवे स्टेशनों के विकास की नींव रखी थी। आज इनमें से 103 स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले 100 स्टेशन की 8 माह में बनकर तैयार हो जाएंगे।

पाकिस्तान ने एक भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने को कहा

इस्लामाबाद, 22 मई। भारत के दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिये जाने के 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने गुरुवार को जवाबी कदम उठाते हुये, यहां स्थित भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को अवांछित घोषित कर पाकिस्तान छोड़ने को कहा है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, संबंधित कर्मचारी को विशेषाधिकार से विपरीत गतिविधियों में लिप्त पाया गया है।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को विदेश मंत्रालय में बुलाकर उसे सरकार के इस निर्णय से अवगत करा दिया है। इस राजनयिक को 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय उच्चायोग का कोई भी अधिकारी उसे प्राप्त विशेषाधिकार का किसी भी तरह दुरुपयोग नहीं कर सकता।

गौरतलब है कि बुधवार को भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी को अवांछित घोषित करते हुये, उसे 24 घंटे के अंदर देश छोड़ देने को कहा था।

नाबालिग से दुष्कर्म करने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि वह सुबह मजदूरी करने गया था। तभी करीब 11 बजे उसकी पत्नी ने उसे घर बुलाया और बताया कि पड़ोसी विजय ने उसकी नाबालिग बेटी की अश्लील वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिये हैं। परिजनों के पूछने पर पीड़िता ने बताया कि एक महीने पहले जब घर पर कोई नहीं था तो विजय ने उसे अपने कमरे पर किसी काम के बहाने से बुलाया था। इस दौरान ही उसने परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो बना लिया। वह फोटो व वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर और संबंध बनाना चाहता था, लेकिन पीड़िता ने मना कर दिया। इस पर उसने 19 जून को इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसकी जानकारी पड़ोस में रहने वाले अन्य लड़के ने दी। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।

सतपाल मलिक के खिलाफ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस प्रोजेक्ट से संबंधित थी।

एजेंसी द्वारा गत वर्ष तलाशी अभियान चलाये जाने के बाद, मलिक ने भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया था।

मलिक ने कहा था कि जिन लोगों के बारे में उन्होंने (मलिक) शिकायत की थी तथा जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उनकी जांच-पड़ताल किये जाने के बजाय, सी बी आई ने उनके आवास पर रेड डाली है। उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट किया था, “उन्हें (सी बी आई को) 4-5 कुर्तों-पाजामा के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, मैं न तो डरूंगा और न झुकूंगा।” केन्द्रीय एजेंसी ने ‘चिनोब

वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सी बी पी पी पी एल) के तत्कालीन चेयरमैन नवीन कुमार चौधरी, तथा अन्य अधिकारियों, जिनमें एम एस बाबू, एम के भित्तल तथा अरुण कुमार मिश्रा शामिल हैं, के अलावा निर्माण-फर्म पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को आरोपी बनाया है।

एफ आई आर में आरोप लगाया गया है, “उस समय चल रही टेन्डरिंग प्रक्रिया के रह हो जाने के बाद, सी बी पी पी पी एल की 47 वीं बोर्ड मीटिंग में ई-टेन्डरिंग और रिवर्स ऑक्शन के जरिये फिर से निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन (48 वीं बोर्ड मीटिंग में लिए एये निर्णय के अनुसार) उस निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया गया था तथा अनंतोगत्वा, टेन्डर पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दे दिया गया था।”

वक्फ एक्ट पर अंतरिम स्टे देने पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित किया

जैसा कि विदित ही है, तीन दिन सुप्रीम कोर्ट में घमासान

बहस चली इस “स्टे” की माँग पर

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की कुछ विवादस्पद धाराओं के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, चुनौती उत प्रावधानों को लेकर दी गई है, जिनमें “उपयोग द्वारा वक्फ (वक्फ बाई यूजर) सम्पत्ति, केन्द्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने, और बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के “विवादित” वक्फ संपत्तियों को छीनने जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ

■ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, हुजेफा अहमदी, चंदर उदय सिंह आदि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने इस बहस में भाग लिया है।

■ रिट दायर करने वाले की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आदि ने दलील दी कि वक्फ एक्ट में संशोधन करने से मुसलमानों के साथ “डिस्क्रिमिनेशन” होगा।

माना जा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवंई और न्यायमूर्ति आंगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 20 मई से शुरू हुई तीन दिवसीय लंबी बहसों के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु

एटा में भारी आंधी तूफान, 5 की मौत

एटा, 22 मई। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान आंधी और वर्षा जनित हादसों में कम से कम पांच लोगों की मृत्यु हो गयी।

पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि एटा के जलेसर तहसील क्षेत्र में एक बायो डीजल को फैक्ट्री की टीनशेड गिरने से उसके नीचे दबकर फैक्ट्री मालिक विवेक प्रताप सिंह (37) एवं उसके कर्मचारी पुष्पेंद्र ऊर्फ पप्पू (43) की मौत हो गयी। एटा की अलीगंज तहसील क्षेत्र के जैथरा थाना क्षेत्र के उदयपुरा गांव में टीन शेड गिरने से उसके नीचे दबकर 19 वर्षीय सुरेन्द्र कुमार सिंह की मौत हो गयी।

एक बार फिर विदेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऐसे माहौल में अगर भारत अमेरिका के दावे को सीधे खारिज करता है, तो डॉनल्ड ट्रंप का उग्र प्रशासन इसे हल्के में नहीं लेगा। जयशंकर बार-बार यह दोहराते रहे हैं कि भारत-पाक संघर्ष केवल तब रुका, जब पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के प्रभारी जनरल ने भारतीय समकक्ष को सीधे कॉल किया।

इस प्रकार, भारत को अमेरिकी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की सबसे खतरनाक प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि वह पाकिस्तान को फिर से सैन्य सहायता

और हथियार देना शुरू कर दे, भारत की स्वतंत्र नीति को सजा देने के लिए। अब देखना यह होगा कि अमेरिका अपनी नाराजगी किस हद तक ले जाता है। लेकिन यह लगभग तय है कि प्रतिक्रिया अवश्य आएगी। ऐसे में भारत को हर संभावित परिदृश्य के लिए तैयार रहना चाहिए।

हालाँकि, भारत जैसे विशाल और महत्वपूर्ण देश को अपनी मूल नीतियों और राष्ट्रीय हितों से पीछे नहीं हटना चाहिए-चाहे धमकी दुनिया के बससे शक्तिशाली देश से हो क्यों न मिले रही हो।

विवाह के तीन माह ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पिता की तरह, आगामी जीवन में उसका संरक्षण करेगा।

विवाह के बाद प्रारंभिक वर्ष में दंपति इन सुखद सपनों के साथ भविष्य की नींव तैयार करते हैं, लेकिन इस मामले में अभियुक्त का कृत्य अपनी पत्नी के प्रति ऐसा रहा कि उसके पास विवाह के तीन माह बाद ही आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। ऐसे में अभियुक्त को कोठारमन दंड से दंडित करना उचित है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेश गजराज ने अदालत को बताया कि अभियुक्त विकास की 12 जून, 2017 को किरण के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी हुई थी। शादी के